मो.एतवारी देवी एवं अन्य

बनाम

मो.पार्वती देवी

17 जनवरी 2006

[अरिजीत पसायत और तरूण चटर्जी, जे.जे.]

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963; धारा 16(सी):

अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा-ट्रायल कोर्ट द्वारा बकाया और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई-उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर उलट दिया गया कि वादी द्वारा प्रस्तुत न तो दलील और न ही सबूत यह साबित करते हैं कि वह अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक था-अपील पर, आयोजित किया गया: वादी द्वारा वादी द्वारा किए गए अनुबंध के अपने हिस्से को निष्पादित करने की तत्परता और इच्छा के संबंध में विशिष्ट कथन-अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में वादी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अनुबंध के अपने हिस्से की पूर्ति के लिए प्रतिफल राशि की पेशकश करने के लिए प्रतिवादी के पास गया था, लेकिन प्रतिवादी अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार नहीं था-इसके अलावा, प्रतिवादी ने ट्रायल कोर्ट या प्रथम अपीलीय

न्यायालय के समक्ष वादी के खिलाफ ऐसी कोई याचिका नहीं उठाई-इसके अलावा, वादी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश और मामले की परिस्थितियों के संदर्भ में प्रश्नगत राशि जमा की। उच्च न्यायालय को प्रतिवादी की मौखिक दलील पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी-इसलिए उच्च न्यायालय का आदेश बचाव योग्य नहीं है।

अपीलकर्ता संख्या के पति ने प्रतिवादी के खिलाफ विशिष्ट निष्पादन के लिए इस आधार पर मुकदमा दायर किया कि प्रतिवादी अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने में विफल रहा था, हालांकि वह अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक था। वादी की मृत्यु हो गई और उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे का फैसला सुनाया, जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय अदालत ने की। व्यथित प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलटते हुए मुकदमा खारिज कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए माना-

1. 1. उच्च न्यायालय के निष्कर्ष रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों के विपरीत हैं। जैसा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने नोट किया है, वादी की अनुबंध की कला को निष्पादित करने की तत्परता और इच्छा के

संबंध में विशिष्ट दावे किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वादी, जिसकी अभियोजन गवाह के रूप में जांच की गई थी, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह प्रतिवादी को पैसे देने के लिए गया था, जो कि बिक्री कार्यों को वापस करने के लिए सहमत नहीं था और इसलिए वादी के लिए एकमात्र रास्ता मुकदमा दायर करना था। अकेले इस आधार पर, उच्च न्यायालय का निर्णय असुरक्षित है। [449-एफ-जी-एच; 450-एआई]

1.2. इस प्रस्ताव से कोई झगड़ा नहीं हो सकता कि अनुबंध के विशिष्ट पालन के मुकदमे में वादी को यह साबित करना होगा, वह अनुबंध की तारीख और मुकदमे की सुनवाई की तारीख के बीच लगातार अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक था। लेकिन यह निष्कर्ष तथ्यात्मक रूप से गलत है कि वादी ने अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने की अपनी क्षमता साबित नहीं की है क्योंकि वह ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार पैसा जमा करने के लिए भी तैयार नहीं था। प्रतिवादी द्वारा पहली अपीलीय अदालत के समक्ष या दूसरी अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई याचिका नहीं उठाई गई थी। हालाँकि, जमा राशि ट्रायल कोर्ट द्वारा अपने फैसले और डिक्री द्वारा दिए गए एक महीने के समय के भीतर ही जमा कर दी गई थी। जमा राशि के बावजूद, समय विस्तार के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। उच्च न्यायालय को आवेदन को नजरअंदाज

करना चाहिए था और उस पर कोई जोर नहीं देना चाहिए था क्योंकि रिकॉर्ड के सत्यापन से पता चल जाता कि भुगतान किया जा चुका है। अन्यथा भी ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए समय के भीतर जमा न करने के बारे में प्रतिवादी द्वारा ऐसी कोई दलील नहीं दी गई थी। उच्च न्यायालय को वर्तमान अपीलकर्ताओं को मामले में अपनी बात रखने का अवसर दिए बिना प्रतिवादी द्वारा की गई मौखिक दलील पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए, उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय बचाव योग्य नहीं है और खारिज किया जाता है। ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को बहाल किया जाता है। [450-बी-सी-डी-ई-एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:

सिविल अपील संख्या 1514/2000

अपीलीय डिक्री संख्या 23/1984 (आर) से अपील में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 11.5.1999 से

अपीलकर्ताओं की ओर से गोपाल प्रसाद।

प्रतिवादी की ओर से के.के.गुप्ता।

न्यायालय का निर्णय **अरिजीत पसायत, जे** द्वारा दिया गया था।

अपील में चुनौतीग्रस्त निर्णय पटना उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश का है, जिसमें कहा गया है कि अपीलकर्ता अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री के हकदार नहीं थे। प्रतिवादी द्वारा दायर दूसरी अपील में, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री को उलट दिया गया और वादी का मुकदमा खारिज कर दिया गया। मूल रूप से यह मुकदमा अपीलकर्ता संख्या 1 के पति, अपीलकर्ता संख्या 5 के पिता नुनु महतो द्वारा दायर किया गया था। नुनु महतो की मृत्यु के बाद उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की कि वादी ने यह साबित नहीं किया है कि वह अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक था। विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 16(सी) की आवश्यकता के संदर्भ में न तो दलील दी गई थी और न ही सबूत पेश किया गया था। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे उच्च न्यायालय का निर्णय कानूनी और सैद्धांतिक रूप से विभिन्न कमजोरियों से ग्रस्त है। प्रतिवादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, हालांकि उसका प्रतिनिधित्व एक वकील ने किया था जो सुनवाई की कई तारीखों पर उपस्थित नहीं हुआ और आज भी उपस्थित नहीं है।

दूसरी अपील उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई और निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए गए, जो उच्च न्यायालय के अनुसार नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा I00 (संक्षेप में कोड') के तहत तैयार किए जाने के लिए आवश्यक कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न थे।

(i) क्या यह निष्कर्ष कि वादी अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक थे, इस बिंदु पर साक्ष्य के अभाव के कारण ख़राब हो गया है?

(i) क्या उपरोक्त बिंदु पर साक्ष्य के अभाव में निचली अपीलीय अदालत द्वारा पारित डिक्री कायम रखने योग्य है?

उच्च न्यायालय ने इस आशय के निष्कर्ष दर्ज किए कि दलीलों में कोई विशिष्ट कथन नहीं था कि वादी अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक था और 1 इस संबंध में कोई सबूत भी नहीं दिया गया था। जैसा कि अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने ठीक ही बताया है, निष्कर्ष रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों के विपरीत हैं। जैसा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादपत्र के विभिन्न अनुच्छेदों में उल्लेख किया है, विशेष रूप से, अनुच्छेद 18 और 22 में अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए वादी की तत्परता और इच्छा के संबंध में विशिष्ट कथन दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वादी नुनु महतो, जिनसे पीडब्लू9 के रूप में पूछताछ की गई थी, ने स्पष्ट

रूप से कहा है कि वह प्रतिवादी को पैसे देने के लिए गए थे, जो कि प्रतिफल है, जो बिक्री विलेख वापस करने के लिए सहमत नहीं था और इसलिए वादी के लिए एकमात्र रास्ता मुकदमा दायर करना था।

अकेले इस आधार पर, उच्च न्यायालय का निर्णय असुरक्षित है। एक अन्य कारक जो उच्च न्यायालय को प्रभावित करता प्रतीत होता है, वह यह है कि भले ही ट्रायल कोर्ट द्वारा वादी को 1500 रुपये की राशि जमा करने के लिए एक महीने का समय दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह फिर से रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों के विपरीत एक निष्कर्ष है। इस प्रस्ताव से कोई झगड़ा नहीं हो सकता कि अनुबंध के विशिष्ट पालन के मुकदमे में वादी को यह साबित करना होगा, वह अनुबंध की तारीख और मुकदमे की सुनवाई की तारीख के बीच लगातार अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक था। लेकिन यह निष्कर्ष तथ्यात्मक रूप से गलत है कि वादी ने अनुबंध का हिस्सा पूरा करने की अपनी क्षमता साबित नहीं की है क्योंकि वह ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार पैसा जमा करने के लिए भी तैयार नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी द्वारा प्रथम अपीलीय अदालत के समक्ष ऐसी कोई याचिका नहीं उठाई गई थी। दूसरी अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपील के ज्ञापन में भी ऐसी कोई दलील नहीं दी गई थी। अभिलेखों को देखने पर, ऐसा

प्रतीत होता है कि जमा 19.12.1978 को किया गया था, जो कि ट्रायल कोर्ट द्वारा अपने फैसले और डिक्री दिनांक 25.11.1978 द्वारा दिए गए एक महीने के समय के भीतर किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रम की स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि जमा राशि के बावजूद, समय विस्तार के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। उच्च न्यायालय को आवेदन को नजरअंदाज कर देना चाहिए था और उस पर कोई जोर नहीं देना चाहिए था, रिकॉर्ड के सत्यापन से पता चलता कि भुगतान किया गया था। अन्यथा भी प्रतिवादी (यहां प्रतिवादी) द्वारा ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए समय के भीतर जमा न करने के बारे में ऐसी कोई दलील नहीं दी गई थी। उच्च न्यायालय को वर्तमान अपीलकर्ताओं को मामले में अपनी बात रखने का अवसर दिए बिना प्रतिवादी, जो उसके समक्ष अपीलकर्ता था, के विद्वान वकील द्वारा की गई मौखिक दलील पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। इस स्थिति से ऊपर, उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय बचाव योग्य नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए, जिसका हम निर्देश देते हैं। अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को बहाल किया जाना है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

एस.के.एस. अपील की अनुमति है।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u> - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।